चना : मांग-आपूर्ति एवं मूल्य आउटलुक 2008

- सार
- परिचय
- आपूर्ति
  - घरेलू उत्पादन
  - कैरी फॉरवर्ड स्टॉक
  - वैश्विक उत्पादन और आयात
- मांग
- मांग-आपूर्ति विश्लेषण
- कीमतों का विश्लेषण

सार

प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्रतिकूल मौसम के कारण देश में इस साल चने का उत्पादन सरकार के 58.3 लाख टन के अनुमान से घटकर 47.5-50.0 लाख टन रहने की आशंका है। उत्पादन में कमी के चलते आयात व कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को मिलाकर देश में चने की कुल उपलब्धता 55.07-57.57 लाख टन के बीच रहने के आसार हैं। जबकि कुछ मांग 60-61 लाख टन के बीच रहने का अनुमान है।

मांग और आपूर्ति में अंतर होने से इस साल देश में चने की कीमतें ऊंचे स्तर पर रहेंगी। इस सीजन में बड़ी कंपनियों की खरीदी, मटर की मिलावट, सरकारी नीतियां, मुद्रास्फीति, लिक्विडिटी, एक्सचेंज रेट, ब्याज दर जैसे बाहरी कारक चने की मांग व कीमतों को प्रभावित करेंगे।

मांग-आपूर्ति और अन्य कारकों को देखते हुए लगता है कि इस साल चने के भाव 2600-3200 रुपए के दायरे में रहेंगे।

परिचय

चना देश की प्रमुख दलहन फसल है। देश के कुल दलहन उत्पादन में चने की भागेदारी 40-45 फीसदी के बीच रहती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चना उत्पादक है। कुल वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 60-65 फीसदी है। भारत में देसी और काबली, दो तरह के चने उपजाए जाते हैं। कुल उत्पादन में देसी और काबुली चना की हिस्सेदारी क्रमश: 85-90 फीसदी और 10-15 फीसदी रहती है।

चना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें तकरीबन 25-29 फीसदी प्रोटीन, 5 फीसदी वसा और 55 फीसदी कार्बोहाइड्रेट होता है। देश में चना का उपयोग सीधे या दाल व बेसन के रुप में होता है।

देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में चना प्रमुख रुप से उगाया जाता है। देश में चने की बोआई सितंबर-नवंबर में होती है और कटाई फरवरी-मार्च के बीच होती है।

भारत दुनिया का सबसे बडा दलहन उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश हैं। देश बड़ी शाकाहारी जनसंख्या के लिए चना सहित अन्य दालें प्रोटीन का सबसे सस्ता और सुलभ जरिया है। देश में दलहनों की मांग काफी रहती है इसलिए सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद देश को काफी मात्रा में दलहनों का आयात करना पड़ता है।

आपूर्ति

घरेलू उत्पादन

घरेलू दलहन उत्पादन की स्थिति देखें तो पिछले 10 साल में देश का दलहन उत्पादन 1.10 करोड़ से 1.49 करोड़ टन के बीच रहा है। इस दौरान पैदावार में काफी उतार-चढ़ाव हुए हैं।

साल 1998-99 में दलहन उत्पादन 1.49 करोड़ टन के ऊंचे स्तर पर था जो 2000-01 में 1.10 टन के निचले स्तर पर आ गए था। हालांकि, साल 2000-01 और 2002-03 को छोड़ दें, जबकि उत्पादन में भारी गिरावट हुई थी, तो पिछले 10 साल में कुल दलहन उत्पादन 1.31 करोड़ टन से 1.49 करोड़ टन के दायरे में रहा है। सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमान को माने तो चालू साल में देश का कुल दलहन उत्पादन पिछले साल से 1.40 लाख टन की मामूली वृद्धि के साथ 1.434 करोड़ टन रहने की संभावना है। हालांकि, इस अनुमान पर सवाल उठाए जा सकते हैं क्योंकि इस साल रकबे में कमी के साथ-साथ भयंकर ठंड और बेमौसम बारिश से कई राज्यों में चने की फसल को काफी नुकसान हुआ जिससे चने के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले लगभग 13 लाख टन की कमी आने की आशंका है। जो कुल दलहन उत्पादन के आंकड़े को गड़बड़ा सकता है। चालू साल में दलहनों के कुल रकबे की बात करें तो क्रॉप वैदर वॉच ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल रबी और खरीफ का कुल 2.58 करोड़ हैक्टेयर रहा है जो पिछले साल के 2.54 करोड़ हैक्टेयर से चार लाख हैक्टेयर अधिक है।

कुल दलहन उत्पादन की तरह ही देश में चने की पैदावार में भी साल दर साल घटबढ़ होती रहती है। मौसम, वैकिल्पक फसलों की लाभदायकता के आधार पर हर साल चने के रकबे और उत्पादन में घटबढ़ होती रहती है। देश में इस साल चने का रकबा पिछले साल से तकरीबन चार लाख हैक्टेयर घटकर 80.34 लाख हैक्टेयर रहने की आशंका है। ऊंचे भावों और अनुकूल मौसम के कारण पिछले साल देश में चने का रकबा 84.02 लाख हैक्टेयर के ऊंचे स्तर पर था। हालांकि, इस साल प्रतिकूल मौसमी स्थिति और चने की कीमतों में सुस्ती के कारण कई हिस्सों में किसानों ने गेहूं और दूसरी वैकिल्पक फसलों को ज्यादा तरजीह दी। विशेषकर सबसे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में चने के रकबे में लगभग 10 फीसदी की गिरावट आई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चना पैदा होता है इसलिए रकबे में 10 फीसदी की गिरावट काफी अहम हो जाती है। इस राज्य में किसानों ने ऊंचे भावों के चलते गेहूं की बोआई ज्यादा की। चने का रकबा कर्नाटक में 7.8 फीसदी और उत्तर प्रदेश में 24.6 फीसदी गिरा है। उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी के कारण रकबे में कमी आई है, यहां सिर्फ उन्ही क्षेत्रों में चना बोया गया जहां सिंचाई की व्यवस्था है। उधर, राजस्थान में चने के क्षेत्र में 11.1 फीसदी की बढ़त देखी गई है, यहां किसानों ने सरसों की बजाय चना को तरजीह दी। राजस्थान के साथ-साथ गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी चने की बोआई ज्यादा हुई है, इन राज्यों में रकबा क्रमश: 7.3, 3.2 और 10.9 फीसदी बढ़ा है।

कुल मिलाकर देखें तो देश में इस साल चने का रकबा लगभग पांच फीसदी कम हुआ है। रकबे में आई कमी का प्रभाव शायद उतना नहीं होता लेकिन प्रतिकूल मौसम ने स्थिति को

और गहरा दिया है। भारी ठंड और पाले ने मध्य प्रदेश के मालवा बेल्ट में चने की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश की कमी के कारण बोआई भी कम हुई है जिससे यहां पैदावार लगभग 20 फीसदी घटकर 18-19 लाख टन रहने की आशंका है। राज्य में उत्पादन में कमी के साथ-साथ चने की क्वॉलिटी भी खराब हुई है। मध्य प्रदेश में आवक शुरु हो गई है और जो माल अभी आ रहा है वह दाल बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। दाना या तो छोटा है या हरा व दागी है। जिसका बेसन में ही इस्तेमाल हो सकता है।

दूसरे बड़े उत्पादक राजस्थान की बात करें तो यहां खराब मौसम के कारण रकबे में वृद्धि के बावजूद चने की पैदावार पिछले साल से लगभग दो लाख टन घटकर सात लाख टन के करीब रहने की आशंका है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी फसल कम होने की आशंका है। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में पैदावार बढ़ने की उम्मीद है।

राज्यवार चना उत्पादन अनुमान साल 2007-08 *

राज्य	उत्पादन लाख टन में
मध्य प्रदेश	18-19
महाराष्ट्र	8-9
राजस्थान	7
उत्तर प्रदेश	3.5
गुजरात	3.0-3.5
आंध्र प्रदेश	3
कर्नाटक	2
छत्तीसगढ़	1
अन्य	2
कुल	47.5-50.0

* कमोडिटीजकंट्रोल डॉट कॉम के अनुमान
** सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2007-08 में 58.3 लाख टन चना पैदा होने का अनुमान है

देश में चना और कुल दलहनों का उत्पादन

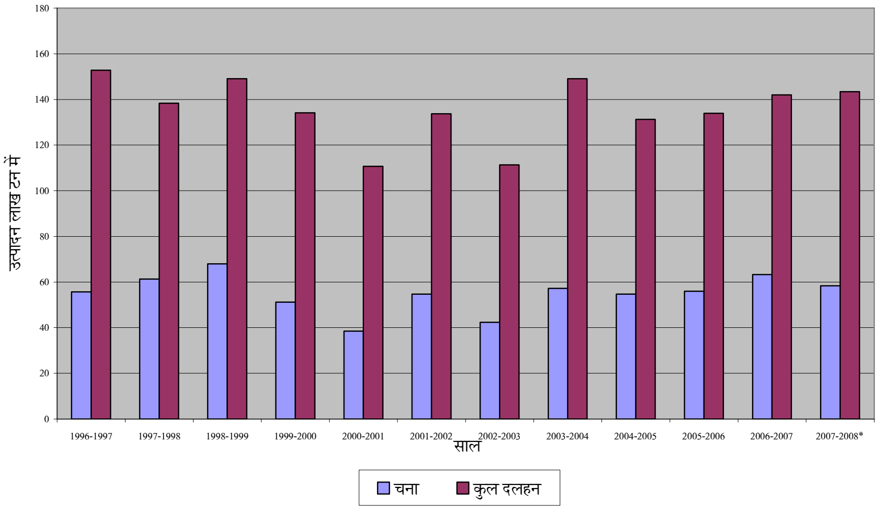

देश में दलहनों का रकबा, उत्पादन और औसत उपज

	चना			सभी दलहन		
साल	रकबा	उत्पादन	औसत उपज	रकबा	उत्पादन	औसत उपज
1996-97	68.50	55.70	813	224.50	142.40	635
1997-98	75.60	61.30	811	228.70	129.80	567
1998-99	84.70	68.00	803	235.00	149.10	634
1999-2000	61.50	51.20	833	211.20	134.20	635
2000-01	51.90	38.60	744	203.50	110.80	544
2001-02	64.20	54.70	853	220.10	133.70	607
2002-03	59.10	42.40	717	205.00	111.30	543
2003-04	70.5	57.2	811	234.6	149.10	635

2004-05	67.1	54.7	815	227.6	131.30	577
2005-06	69.3	56.00	808	223.9	133.90	598
2006-07*	76.3	63.3	-	237.6	142.20	-
2007-2008**	-	58.3	-	-	143.40	-

स्रोत- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार * अंतिम अनुमान ** दूसरा अग्रिम अनुमान, फरवरी, 2008

कैरी फॉरवर्ड स्टॉक

सरकारी अनुमान के मुताबिक साल 2006-07 में देश में 63.3 लाख टन चना पैदा हुआ था। जबकि आयात 1.27 लाख टन रहा था। इस तरह देश में साल 2006-07 के दौरान चने की कुल उपलब्धता 64.57 लाख टन रही। जबकि खपत लगभग 60 लाख टन के करीब रहने की संभावना है। इस तरह चालू साल यानि 2007-08 के लिए कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 4.57 लाख टन के करीब रहता है।

वैश्विक उत्पादन और आयात

चना दुनिया की प्रमुख खाद्य लेग्यूम फसल है। पूरी दुनिया में एक करोड़ हैक्टेयर से ज्यादा रकबे में इसकी बोआई होती है। पिछले पांच साल में दुनिया में चने का उत्पादन (देसी और काबुली दोनों) 70.85-88.32 लाख टन के बीच रहा है। सबसे अधिक चना उत्पादन भारत में होता है। पूरी दुनिया के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 60-65 फीसदी रहती है। साल 2006-07 में चने का वैश्विक उत्पादन 86.5 लाख टन रहा जिसमें से देसी चने की पैदावार 66.45 लाख टन और काबुली चने की पैदावार 20.65 लाख टन रही।

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
रकबा लाख हैक्टेयर में	99	109	105	107	108
औसत उपज टन/हैक्टेयर में	0.72	0.8	0.79	0.82	0.8

ओपिनंग स्टॉक लाख टन में	4	1	4	3	5
उत्पादन लाख टन में					
भारत	42.4	57.2	54.7	56.5	57
टर्की	6.5	6	6.2	6.1	6.1
पाकिस्तान	3.62	6.75	6.11	8.68	4
आस्ट्रेलिया	1.39	1.86	1.23	1.38	3.04
ईरान	3	3.1	3.1	3.1	2.8
मेक्सिको	2.35	2.4	2.4	2.4	2.4
म्यानमार	2.12	2.28	2.3	2.3	2.3
कनाडा	1.56	0.68	0.51	1.04	1.63
इथोपिया	1.87	1.14	1.36	1.35	1.35
इराक	0.97	1.04	1	0.95	1
अमरीका	0.38	0.2	0.27	0.49	0.67
सीरिया	0.89	0.87	0.45	0.55	0.55
स्पेन	0.7	0.51	0.57	0.18	0.4
मोरक्को	0.51	0.43	0.42	0.42	0.4
अन्य	2.59	2.75	2.71	2.88	2.86
कु ल	70.85	87.21	83.33	88.32	86.5
काबुली चना का कुल उत्पादन	21.03	18.85	18.71	19.14	20.05
देसी चना का कुल उत्पादन	49.82	68.66	64.62	69.18	66.45
कुल सप्लाई	74.85	88.21	87.33	91.32	91.5
कुल खपत	73.85	84.21	84.33	86.32	86.5
क्लोजिंग स्टॉक	1	4	3	5	5
स्टॉक और उपयोग अनुपात % में	1	5	4	6	6

स्रोत- विभिन्न सरकारी और बहुपक्षीय संस्थायें

* अनुमानित

साल 2007-08 की बात करें तो भारत के उत्पादन में भारी गिरावट के कारण चने की वैश्विक पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम रहने की आशंका है। भारत के अलावा टर्की और पाकिस्तान में भी चना की पैदावार कम होने की आशंका है। जबकि आस्ट्रेलिया और कनाडा में उत्पादन बढ़ेगा। चालू साल में टर्की का उत्पादन पिछले साल के 6.1 लाख टन से 7.2 फीसदी कम होने के आसार हैं। पाकिस्तान को देखें तो वहां उत्पादन 8.48 लाख टन (पाकिस्तान सरकार के ताजा अनुमान, अन्य एजेंसियों के मुताबिक इस देश में उत्पादन चार लाख टन अनुमानित है) से घटकर 7.61 लाख टन रहने का अनुमान है। पाकिस्तान और टर्की घरेलू खपत, उत्पादन से कम रहने की संभावना है जिससे इन दोनों देशों में निर्यात के लिए सरप्लस माल उपलब्ध रहेगा। हालांकि, पाकिस्तान ने दाल निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है जिससे यहां से आयात की संभावना नहीं है।

आस्ट्रेलिया में चने की पैदावार 2.32 लाख टन से बढ़कर 3.13 लाख टन रहने की संभावना है। लेकिन निर्यात घटकर 1.96 लाख टन रहने का अनुमान है। कनाडा में इस साल चने की पैदावार पिछले साल के 1.63 लाख टन से बढ़कर 2.25 लाख टन होने की उम्मीद है और निर्यात 1.15 लाख से बढ़कर 1.25 लाख टन रहने की संभावना है।

बाकी चना उत्पादक देशों में उत्पादन सामान्य रहने की संभावना है। लेकिन म्यानमार, ईरान, मेक्सिको और इथोपिया के अलावा अन्य देशों से चने के आयात की संभावना नहीं है। इन देशों से भी सीमित मात्रा में चने का आयात हो सकता है।

भारत में चने की कमी को देखते हुए साल 2007-08 में चना आयात पिछले साल के 1.27 लाख टन बढ़कर तीन लाख टन रहने की संभावना है।

चना और कुल दलहन आयात

दलहन	साल देश	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07
		टन में				
चना	आस्ट्रेलिया	12,538	44,476	13,917	58,350	74,882
	ईरान	57,026	32,208	56,455	30,509	0
	म्यानमार	35,459	62,550	21,725	17,597	25,710
	पाकिस्तान	75	25,683	425	122,316	22
	कनाडा	59,810	50,055	10,251	4,986	7,982
	अन्य	52,646	44,269	30,103	47,998	18,722
चना	कुल	217,553	259,239	132,875	281,756	127,318
कुल दलहन		1,266,480	2,157,648	1,586,892	1,944,837	2,822,359

स्रोत:विदेश व्यापार महानिदेशालय

मांग

भारत में दालें सदियों से आम लोगों की प्रोटीन जरुरत को पूरा का सबसे सस्ता और सुलभ जरिया रहा है। शायद इसका बड़ा कारण देश में शाकाहार का ज्यादा प्रचलन है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद के दशकों में देश में दालों की प्रति व्यक्ति खपत में भारी कमी आई है और तय पोषण मानदंड से काफी नीचे चली गई है। इस दौरान जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। बढ़ती जनसंख्या की भोजन की मांग को पूरा करने के लिए ग्रीन रिवॉल्युशन के बाद अधिकतर खाद्यान के उत्पादन में जोरदार वृद्धि देखने को मिली लेकिन दालों का उत्पादन काफी धीमी गति से बढ़ा है। सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए हैं लेकिन उत्पादन में फिर खास प्रगति नहीं हुई है।

देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही तेज आर्थिक विकास के कारण लोगों की आय भी बढ़ रही है। इसका नतीजा अन्य खाद्य पदार्थों के अलावा दालों की खपत में वृद्धि के रुप में देखने को मिल रहा है।

अन्य दालों की तुलना में देश में चना सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 60-65 फीसदी चने का इस्तेमाल बेसन के रुप में होता है जबकि 15-20 फीसदी चना दाल के तौर पर इस्तेमाल होता है। बाकी 20 फीसदी हिस्सा बोआई और सीधे उपयोग के काम आता है।

भारत की बड़ी शाकाहारी जनसंख्या के लिए चना प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसमें 25-29 फीसदी प्रोटीन होता है।

बढ़ती जनसंख्या, दायरेबंद उत्पादन और भारी आयात के बीच देश में दालों की प्रति व्यक्ति खपत घटती जा रही है। पिछले 11 सालों के आंकड़े देखें तो कुल दालों की खपत 13.5 से 10.6 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रही है। जबकि चना की खपत 5.3 से 2.9 किलो के बीच रही है। पिछले 11 सालों के दौरान वर्ष 2001 में उत्पादन में कमी के कारण चना समेत सभी दलहनों की उपलब्धता सबसे कम रही है।

भारतीय उपभोक्ता काफी मूल्य संवेदी हैं। आय में वृद्धि के बावजूद वैकिल्पक खाद्य पदार्थों की तुलना में दालों के दाम ऊंचे होने के कारण इनकी खपत पर असर पड़ते दिखा है। मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग दालों के भाव ज्यादा होने पर सस्ते अनाज और सब्जियों की ओर रुख कर लेते हैं। जबकि उच्च आय वर्ग दाल को छोड़ सब्जियों, फलों, डेयरी उत्पाद और मांस की तरफ मुड़ जाता है।

साल 2003 से 2006 के बीच देश में दालों के उत्पादन और खपत की औसत वृद्धि दर क्रमश: -1.96 और +3.41 फीसदी रही। उत्पादन और खपत में खासे अंतर के कारण देश भारी मात्रा में दालों का आयात करना पड़ा।

साल	चावल	गेहूं	अन्य अनाज	कुल अनाज	चना	दालें	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न
	किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष						
1996	74.6	64.3	22.6	161.5	4.1	12.0	173.5
1997	78.1	65.4	26.6	170.1	4.5	13.5	183.6
1998	73.1	55.3	22.8	151.2	4.9	12.0	163.2
1999	74.2	59.2	23.1	156.7	5.3	13.3	170.0
2000	74.3	58.4	21.5	154.3	3.9	11.6	165.9

2001	69.5	49.6	20.5	141.0	2.9	10.9	151.9
2002	83.5	60.8	23.1	167.4	3.9	12.9	180.4
2003	66.2	65.8	17.1	149.1	3.1	10.6	159.7
2004	71.3	59.2	25.3	155.8	4.1	13.1	168.9
2005	64.7	56.3	21.7	142.7	3.9	11.5	154.2
2006 [1]	72.3	56.0	22.1	150.4	-	11.8	162.3

स्रोत- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

देश में चालू साल में दालों की कुल खपत 1.6 करोड़ टन अनुमानित है जबकि चने (देसी और काबुली दोनों) की खपत 60-61 लाख टन के बीच रहने की संभावना है। घरेलू स्तर पर दालों के उत्पादन में कोई खास बढ़त न होने और बढ़ती मांग व कीमतों को मद्देनजर आयात काफी बढ़ा है साल 2006-07 में लगभग 28 लाख टन दालों का आयात हुआ। हालांकि, पिछले चना का उत्पादन अधिक होने से इसके आयात में कमी आई और यह 1.27 लाख टन रहा। साल 2007-08 में 30 लाख टन से ज्यादा दलहन के आयात की संभावना है। वैसे तो उत्पादन में भारी कमी के कारण साल 2007-08 में चने के भारी आयात की जरुरत पड़ेगी लेकिन निर्यातक देशों में चने की उपलब्धता को देखते हुए आयात पिछले साल के 1.27 लाख टन के मुकाबले तीन लाख टन के करीब रहने की संभावना है।

मांग-आपूर्ति विश्लेषण

देश में चालू साल में चने का उत्पादन 47.5-50 लाख टन रहने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा दालों के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण देश से चने का निर्यात नहीं हो पाएगा। इसलिए देश का पूरा उत्पादन घरेलू खपत के लिए उपलब्ध होगा। उत्पादन के इस आंकड़े में हम 4.57 लाख कैरी फॉरवर्ड स्टॉक और तीन लाख टन आयात को जोड़ दें तो घरेलू बाजार में चने की कुल आपूर्ति 55.07-57.57 लाख टन के करीब रहेगी। जबकि मांग 60-61 लाख टन रहने का अनुमान है।

बैलेंस शीट साल 2008*

ओपिनंग स्टॉक	4.57
उत्पादन	47.5-50
आयात	3
कुल सप्लाई	55.07-57.57
मांग	60-61
अंतिम स्टॉक	0

सभी आंकड़े लाख टन में

* कमोडिटीजकंट्रोल डॉट कॉम के अनुमान

कीमतों का विश्लेषण

पिछले साल भारी उत्पादन के बाद चने के भाव में लंबे समय तक सुस्ती बनी रही। लेकिन उत्पादन में कमी की आशंका के कारण इस साल जनवरी से कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है। दिल्ली में चने के हाजिर भाव जनवरी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे थे लेकिन फरवरी में भाव 2800 रुपए के ऊंचे स्तर तक चले गए, इसके बाद से कीमतें छुटपुट करेक्शन बाद ऊपरी स्तर बनी हुई हैं।

अगर अनुमानित बैलेंस शीट को देखते हुए देश में 2008-09 के दौरान चने की काफी कमी रहने की आशंका है जिससे इसकी कीमतें तेज रहेंगी।

कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में चने की जोरों से आवक हो रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आवक ने अब जोर पकड़ना शुरु किया है। मांग में सुस्ती और आवक को देखते हुए मई महीने के अंत तक चने के भाव कुछ नरम रहने की आशंका है। इस दौरान कीमतों में 100-150 रुपए का करेक्शन आ सकता है।

लेकिन जून से मांग बढ़ने के कारण कीमतों में तेजी बन जाएगी जो बाकी सीजन में बनी रहेगी। हालांकि, तंजानिया से अगस्त-सितंबर और आस्ट्रेलिया से दिसंबर में आयातित चना पहुंचने की वजह से कीमतों में इस दौरान हल्की नरमी देखी जा सकती है।

मांग-आपूर्ति और अन्य कारकों को देखते हुए लगता है कि इस साल चने के भाव 2600-3200 रुपए के दायरे में रहेंगे। फिलहाल दिल्ली में चने के भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल है।

मांग-आपूर्ति के सामान्य कारकों के अलावा बड़ी कंपनियों की खरीदी, मटर की मिलावट, सरकारी नीतियां, मुद्रास्फीति, लिक्विडिटी, एक्सचेंज रेट, ब्याज दर जैसे बाहरी कारक इस सीजन में चने की मांग व कीमतों को प्रभावित करेंगे।

बड़ी कंपनियों की खरीदी का प्रभाव

पिछले साल की तरह ही इस साल भी बड़ी कंपनियों द्वारा चने की भारी खरीदी की संभावना है। मध्य प्रदेश, जहां चने की आवक शुरु हो गई है, में कुछ कंपनियां लेवाली में सक्रिय हो गई हैं। बड़ी कंपनियां अपनी आर्थिक ताकत के बूते लंबे समय तक स्टॉक होल्ड कर लेती हैं और कीमतों के मुताबिक माल की निकासी करती हैं। बड़ी कंपनियों अगर बड़ी मात्रा में चने का भंडार करती हैं तो इससे कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

मटर की मिलावट

सफेद मटर की पर्याप्त उपलब्धता और कम कीमत के कारण इसका इस्तेमाल चना दाल व बेसन में मिलावट के लिए काफी होता है। विशेषकर चना की पैदावार कम होने पर मिलावट बढ़ जाती है। इससे चने की कीमतों पर नकारात्मक असर पड़ता है। मार्च, 2008 के तीसरे हफ्ते में सफेद मटर के भाव 2200-2250 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर थे जबकि इस दौरान दिल्ली में चने के भाव 2650-2700 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर थे। इस तरह इन दोनों दलहन के भाव में लगभग 400 रुपए का अंतर था। अगर इन दोनों दालों की कीमतों में बड़ा अंतर बना रहता है तो इससे चना दाल और बेसन में मटर की मिलावट बढ़ सकती है और चने भाव पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

वैसे देश में इस साल मटर का उत्पादन कम हुआ है लेकिन कनाडा और अमरीका में पर्याप्त उत्पादन के कारण इन देशों से सफेद मटर का आयात बढ़ सकता है। साल 2006-07 में देश में 13.88 लाख मटर का आयात हुआ था।

मेक्रो इकॉनॉमिक कारक

चने की मांग और कीमतें मेक्रो इकॉनॉमिक कारकों से अछूती नहीं हैं। हालांकि, आर्थिक विकास दर और कुल निजी उपभोग खर्च में दालों की हिस्सेदारी देखें तो इसमें कोई खास

तारतम्य नहीं दिखता, यही स्थिति चने के लिए भी मानी जा सकती है। लेकिन मुद्रास्फीति ब्याज दर जैसे कारक मांग और कीमतों को जरुर प्रभावित करते हैं।

ऊंची विकास दर के बावजूद साल 2005-06 में कुल निजी उपभोग खर्च में दालों की हिस्सेदारी 1.1 फीसदी के स्तर पर रही। लेकिन साल 2002-03 में विकास दर 3.8 फीसदी के निचले स्तर पर रहने के बावजूद निजी उपभोग खर्च में दालों की हिस्सेदारी 1.2 फीसदी रही।

इससे संकेत मिलता है कि अगर आशंका के अनुरुप देश की विकास दर में कमी आती है तो सिर्फ इसके कारण चना सहित अन्य दालों की खपत पर नकारात्मक असर पड़ने के आसार कम हैं। लेकिन मुद्रास्फीति में वृद्धि और इसके परिणामस्वरुप ब्याज दरों में होने वाले बदलाव तथा रुपए की विनिमय दर घटबढ़ दालों की मांग और कीमतों पर असर डाल सकती हैं। अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना रहेगी जिससे कुल मिलाकर कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रुपए कमजोरी आती है, जैसा कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो इससे घरेलू बाजार में आयातित चने के भाव तुलनात्मक रुप से अधिक होंगे।

सरकार ने साल 2008-09 के बजट में लगभग 60 हजार करोड़ के ऋण माफी पैकेज की घोषणा की है। इसके चलते किसानों के पास अतिरिक्त धन रहने की संभावना है। किसानों के अपने पास मौजूद अतिरिक्त धन से अन्य चीजों के अलावा भोजन खर्च में भी वृद्धि हो सकती है जो चना सहित सभी दालों की मांग और कीमतों में वृद्धि के लिए सकारात्मक रहेगा।

निजी उपभोग में दालों की हिस्सेदारी और आर्थिक विकास दर

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडीचर में दालों का प्रतिशत स्थिर मूल्य पर	1.2	1.4	1.2	1.4	1.2	1.1	1.1
जीडीपी वृद्धि दर फैक्टर कॉस्ट पर	4.4	5.8	3.8	8.5	7.5	9.4	9.6

स्रोत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

सरकारी नीतियां - बढ़ती कीमतें सरकार के लिए चिंता का सबब

उत्पादन में कमी और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू स्तर पर भी दालों के भाव बढ़े हैं। साल 2004-05 से 2006-07 के बीच दालों का थोक मूल्य सूचकांक 45.6 फीसदी बढ़ा है जबकि अनाजों का सूचकांक 12 फीसदी बढ़ा है। इस दौरान चने के थोक मूल्य सूचकांक में 51 फीसदी की वृद्धि देखी गई।

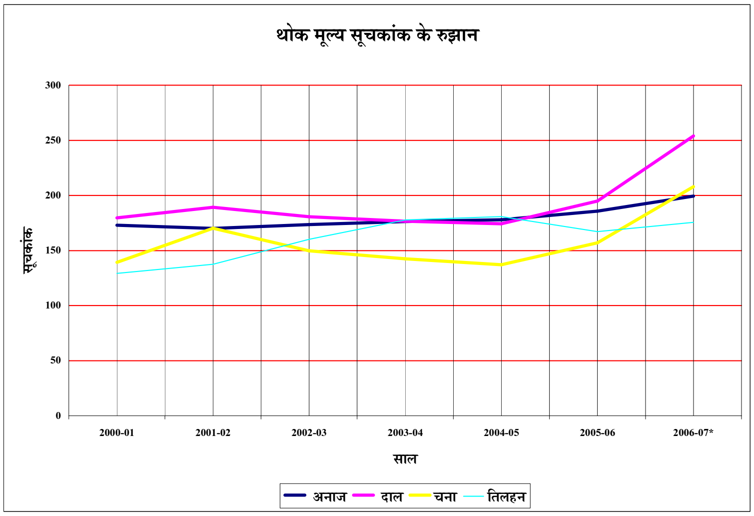

थोक मूल्य सूचकांक

कमोडिटी	भार	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
खाद्यान	5.01	173.8	172.4	174.3	176.3	177.5	187.0	205.9
(अ) अनाज	4.41	173.0	170.1	173.5	176.3	177.9	185.8	199.3
चावल	2.45	167.5	167.0	166.0	168.8	168.2	174.5	179.6
गेहूं	1.38	176.6	175.3	175.7	181.4	184.1	191.5	216.4
(ब) दाल	**0.60**	**179.6**	**189.2**	**180.6**	**176.6**	**174.4**	**194.9**	**253.9**
चना	0.22	139.2	170.3	149.7	142.5	137.1	157.0	208.0
तुअर	0.13	150.3	142.6	157.5	172.8	179.3	170.8	182.1
मूंग	0.11	186.9	205.6	208.0	195.9	187.4	219.2	302.8

मसूर	0.04	206.8	203.9	214.1	233.4	234.7	242.8	253.5
उड़द	0.10	295.7	273.9	239.8	217.4	216.3	270.4	404.0
खाद्य पदार्थ	15.40	170.5	176.1	179.2	181.5	186.3	195.3	210.6
गैर-खाद्य पदार्थ	6.14	146.5	152.9	165.4	186.3	187.6	179.1	187.9
तिलहन	2.66	129.3	137.6	160.2	177.8	180.8	167.1	175.6
खाद्य तेल	2.75	103.3	112.9	138.0	157.9	156.4	146.0	154.7

स्रोत : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

दालों की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं लेकिन इनका ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। ये उपाय निम्नानुसार हैं-

- सरकार ने अगले चार साल में अतिरिक्त 80 लाख टन गेहूं, एक करोड़ टन चावल और 20 लाख टन दलहन पैदा करने के उद्देश्य से हाल में ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरु किया है।
- सरकार ने चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2006-07 के 1445 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए, तुअर का 1410 रुपए से बढ़ाकर 1550 रुपए, मूंग और उड़द का 1520 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है।
- साल 2007 की शुरुआत में सरकार ने तुअर और उड़द के वायदा पर रोक लगा दी थी।
- सरकार ने अगस्त, 2006 में दालों पर स्टॉक लिमिट लगा दी थी।
- जून, 2006 को सरकार ने काबुली चना को छोड़कर बाकी सभी दालों के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया।
- सरकार ने जून, 2006 में दालों के आयात पर लगने वाली 10 फीसदी ड्यूटी को खत्म कर दिया।
- सरकारी एजेंसियों के द्वारा दालों आयात पर 15 फीसदी की सब्सिडी ।
- सरकारी एजेंसियों को दालों का आयात बढ़ाने को कहा।

चुनावी साल होने से बढ़ती मुद्रास्फीति सरकार के लिए सरदर्द बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक में मार्च, 2008 को समाप्त सप्ताह में इससे पहले के हफ्ते के 5.02 फीसदी की तुलना में 5.11 फीसदी का इजाफा हुआ। मुद्रास्फीति बढ़ने में खाद्य पदार्थों का योगदान

खासा है इसलिए सरकार इन पदार्थों की कीमतों को अंकुश में रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 17 मार्च, 2008 को संसद में कहा कि हम मुद्रास्फीति पर अंकुश और आर्थिक विकास दर नौ फीसदी के स्तर पर बनाए रखने के लिए सभी जरुरी वित्तीय और मौद्रिक उपाय करेंगे।

इसी वक्तव्य के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब उपभोक्ताओं के लिए कीमतें नीचे रखने के लिए चुनिंदा रुप से ज्यादा खाद्य सब्सिडी दे सकती है।

आने वाले समय में अगर चना सहित अन्य दालों की कीमतों में वृद्धि होती है तो सरकार इन्हे दबाने का प्रयास कर सकती है। इन प्रयासों में सब्सिडी, डिहोर्डिंग और आयात में वृद्धि शामिल हो सकते हैं।

सब्सिट्यूशन

चने के उत्पादन में कमी और कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर उपभोक्ता दूसरी सस्ती दालों या अन्य खाद्य पदार्थों की ओर रुख कर सकते हैं जिससे चने की खपत और कीमतों पर असर पड़ेगा।